

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी साहब आप बैठ जाइये इस तरीके से आप नहीं उठा सकते हैं ।

श्री मोर्य : अध्यक्ष महोदय, 50,000 से भी ज्यादा पैम्पलैट्स प्रधान मंत्री के चरित्र पर आरोप करते हुए किसी पार्टी ने छपवाये । पार्टी यह कहती है कि हम ने नहीं छपवाये । इस के अतिरिक्त अभी भी ऐसा लगता है कि उस काम में 100 से अधिक आदमी लगे हुए नजर आते हैं । उस में किसी विरोधी दल का हाथ नहीं है सरकारी दल के लोगों का ही उस में हाथ है । सरकारी नौकर भी उन्में मिले हुए नजर आते हैं । . . . . उस के बारे में आप को . . . .

Mr. Speaker: Order, order, Mr. Maurya might sit down. He cannot raise these things in this manner. I am repeating it every day twice or thrice. He should not raise these things in this manner.

श्री मोर्य : \* \* \*

अध्यक्ष महोदय : यह रेकार्ड में नहीं जायेगा ।

Mr. Speaker: Mr. Jagjivan Ram:

12.22 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

#### INDUSTRIAL DISPUTES (CENTRAL) AMENDMENT RULES, 1966.

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): I beg to lay on the Table a copy of the Industrial Disputes (Central) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1253 in Gazette of India dated the 13th August, 1966

under sub-section (4) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947. [Placed in Library. See No. LT-6954/66]

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्सो से व्यवस्था के प्रश्न पर प्वाएंटे आफ आर्डर पर खड़ा हो रहा हूं । मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन को बोल लेने दीजिए ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I wish to speak on the paper just laid on the Table.

Mr. Speaker: Yes.

Shri S. M. Banerjee: This is a copy of the Industrial (Central) Amendment Rules, published in Notification No. G.S.R. 1253 in Gazette of India dated the 13th August, 1966, under sub-section (4) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947. I want a clarification from the hon. Minister. I want to know whether in the State of U.P., despite the anti-people ordinance issued by the Governor, the Industrial Disputes Act, 1947, which is applicable to Central Government employees, will be applicable or not even in the matter of strikes and industrial disputes. This is a matter which has not been clarified by the Ordinance.

Mr. Speaker: We are not concerned with that.

Mr. Banerjee is asking for a clarification whether this remains operative there or not.

Shri Jagjivan Ram: I could not follow him.

Shri S. M. Banerjee: You rejected the adjournment motion, Sir. . . . .

Mr. Speaker: He should not bring that adjournment motion here. He may ask for the clarification that he wanted.

**Shri S. M. Banerjee:** Under the Industrial Disputes Act, there are two things: one by the State and the other, by the Centre. My contention is this. While promulgating the Ordinance, the Governor must have consulted either the State or the Central Government. There are 40,000 or 50,000 Central Government employees in some places. The industrial disputes are going on. We have not taken recourse to strike, but we want adjudication or arbitration under the Industrial Disputes Act. I want a clear answer from the hon. Minister on this point: in spite of the fact that there is an Ordinance in U.P.—we may like it or may not like it—what will be the condition of the Central Government employees in U.P.? I want a definite reply.

**Shri Jagjivan Ram:** I am not quite clear about this, but I will get this matter examined. I feel that so far as the Central sphere is concerned, the Industrial Disputes Act will prevail and we will be in a position to deal with labour disputes under the Industrial Disputes Act.

**Shri S. M. Banerjee:** Sir, it is very important....

**Mr. Speaker:** I have already allowed him.

**Shri S. M. Banerjee:** I want to know whether it will be applicable to the Central Government employees there....

**Mr. Speaker:** He says that he is not clear about it and that he will get it examined (*Interruptions*)

12.25 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICES—*contd.*

**अध्यक्ष महोदय:** मेरे मना करने के बावजूद श्री अग्रर कोई बोले चले जायेंगे तो यह ऐकशन लेना पड़ेगा।

**श्री मधु लिमये:** मैं एक असें से अपने व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो रहा हूँ इसलिए मुझे कृपया सुन लिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय:** मेरा प्रश्न संविधान की धारा 239 और नियम 18 के बारे में है। मैं ने एक त्रिपुरा सम्बन्धी कामरोको प्रस्ताव दिया है। चार मंत्रालयों का उस में सम्बन्ध आता है एक तो खाद्य मंत्रालय का सम्बन्ध आता है कि चावल उन्होंने सप्लाय नहीं किया। किरोसीन का मामला है....

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं क्या कहूँ ?

**श्री मधु लिमये:** मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे एक मिनट के लिए सुनिए कि इस में केन्द्र की कैसे जिम्मेदारी आती है और उस के बाद आप अपना इस पर फैसला दे दीजिएगा।

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं मैं इस तरीके से नहीं सुनूँगा। मैं ने कामरोको प्रस्ताव नामंजूर किया है।

**श्री मधु लिमये:** आप मुझे सुन तो लें क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि इस में सेंटर की जिम्मेदारी आती है चूँकि वह केन्द्र शासित प्रदेश है....

**अध्यक्ष महोदय:** जब मैं उस को नामंजूर कर चुका हूँ तो फिर हाउस में उस पर यह डिस्कशन नहीं होगा।

**श्री मधु लिमये:** पहले हुआ है और आप ने हम लोगों को सुना है। आप सुन लीजिए और बाद में फैसला दे दीजिएगा।

**अध्यक्ष महोदय:** यहाँ इस तरह से डिस्कशन नहीं होगा। आप उस बारे में बेशक मुझे लिख कर दे सकते हैं या मुझ से मिल सकते हैं लेकिन यहाँ इस तरह से डिस्कशन नहीं होगा।

12.26 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

ANNUAL ACCOUNTS OF VISAKHAPATNAM PORT TRUST AND AUDIT REPORT THEREON

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): I beg to lay on the Table a